

आरएनआर प्रति माँड कोहली से पहले, जे,

अमृतपाल सिंह एएम) अन्य-मटोर

बनाम

हरियाणा राज्य - उत्तरदाता

2009 का सीडब्ल्यूपी नंबर 9773

3 अगस्त. 2010

भारत का संविधान, 1950-कला. 226-हरियाणा शिक्षा (कॉलेज कैडर) ग्रुप ए \* सर्विस राइड्स, 1986-रिस. 3,7 एवं 9- विकलांग व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995- धारा 47- व्याख्याता के रूप में दो नेत्रहीन व्यक्तियों की नियुक्ति- वरिष्ठता के आधार पर प्राचार्य के पद पर पदोन्नति- 8 का रूपांतरण शारीरिक रूप से विकलांग व्याख्याताओं (नेत्रहीन) के पदों को प्रधानाचार्य (अकादमिक) में - याचिकाकर्ताओं ने परिवर्तित पदों के खिलाफ अपनी परिलब्धियों को कम किए बिना पोस्ट किया - प्रत्यावर्तन के समान - 1986 में प्रधान शैक्षणिक का कोई पद विद्यमान नहीं - सरकार नेत्रहीनों की आरक्षित श्रेणी से प्रधानाचार्यों के पदों को भर रही है -प्रधानाचार्य के रूप में अपने कर्तव्यों का पालन करने में नेत्रहीन व्यक्तियों की असमर्थता की दलील -प्रधानाचार्य के पद पर नियुक्ति के लाभ से इनकार करना अस्वीकार्य - विकलांग व्यक्तियों के लिए एक अलग प्रकार का पद सृजित करने के लिए धारा 33 के प्रावधान के तहत एक वैधानिक अधिसूचना जारी करना आवश्यक है या भर्ती नियमों में संशोधन करें - उत्तरदाताओं द्वारा ऐसी कोई अधिसूचना जारी नहीं की गई है - याचिकाकर्ताओं को कानून में निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए बिना केवल उनकी विकलांगता के आधार पर अन्य पदोन्नत प्राचार्यों के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है - याचिका स्वीकार की गई, प्रत्यावर्तन आदेश रद्द कर दिए गए।

माना गया कि प्रशासनिक निर्देश वैधानिक प्रावधानों पर हावी नहीं हो सकते या उनकी जगह नहीं ले सकते। यदि, सरकार का इरादा इन पदों को धारा 33 के दायरे से बाहर लाकर विकलांग व्यक्तियों के लिए एक अलग प्रकार का पद सृजित करने का था, तो धारा 33 के प्रावधानों या भर्ती के नियमों के तहत एक वैधानिक अधिसूचना जारी करना उचित था। संशोधन किया जाना चाहिए था. हालाँकि, उत्तरदाताओं ने कानून का उल्लंघन करते हुए पदों को परिवर्तित करने के लिए केवल प्रशासनिक निर्देश जारी किए। इस तरह का सहारा कानून द्वारा उचित नहीं है। इस प्रकार, विवादित संचार इस आधार पर भी खारिज किए जाने योग्य हैं।

(पैरा 11)

इसके अलावा, यह माना गया कि अधिनियम की धारा 47 सरकारी रोजगार में विकलांग व्यक्तियों के खिलाफ भेदभाव पर रोक लगाती है। धारा 47 की उपधारा 2 में स्पष्ट रूप से प्रावधान है कि किसी व्यक्ति को केवल उसकी विकलांगता के आधार पर पदोन्नति से वंचित नहीं किया जा सकता है। भले ही, किसी प्रतिष्ठान में किसी विशेष पद के लिए विकलांग व्यक्ति को केवल विकलांगता के कारण पदोन्नति से वंचित किया जाता है, यह केवल वैधानिक अधिसूचना के माध्यम से धारा 47 के प्रावधानों से प्रतिष्ठान को छूट प्रदान करके किया जा सकता है। वास्तव में उसी प्रक्रिया का पालन किया जाना है जो धारा 33 के प्रावधानों के तहत निर्धारित है। इस धारा के तहत भी ऐसी कोई अधिसूचना जारी नहीं की गई है। याचिकाकर्ताओं के साथ कानून में निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए बिना केवल उनकी विकलांगता के आधार पर अन्य पदोन्नत प्रधानाध्यापकों के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है।

(पैरा 12)

याचिकाकर्ताओं के वकील केएल अरोड़ा ।

आरएस कुंडू, अतिरिक्त। एजी, हरियाणा।

परमोद कोहली, जे. (मौखिक) :

(1) दोनों याचिकाकर्ता अंधे हैं। संगीत में बीए और एमए की योग्यता प्राप्त करने पर, उन्हें शुरू में तदर्थ आधार पर व्याख्याता के रूप में नियुक्त किया गया और उसके बाद नियमित किया गया और सेवा में पुष्टि की गई। व्याख्याता के रूप में 25 वर्ष से अधिक की सेवा पूरी करने पर और उनकी वरिष्ठता और योग्यता के आधार पर उन्हें 30 दिसंबर, 2008 के आदेश के तहत कई अन्य व्याख्याताओं के साथ प्रिंसिपल के रूप में पदोन्नत किया गया था। उनकी पदोन्नति स्वीकृत उपलब्ध रिक्तियों के विरुद्ध थी। अपनी पदोन्नति पर, याचिकाकर्ताओं ने अपने-अपने तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण कर लिया। याचिकाकर्ता नंबर 1 ने 2 जनवरी, 2009 को प्रिंसिपल के रूप में कार्यभार ग्रहण किया, जबकि याचिकाकर्ता नंबर 2, 1 जनवरी, 2009 को शामिल हुए। जबकि याचिकाकर्ता अपनी पोस्टिंग के स्थान पर प्रिंसिपल के रूप में काम कर रहे थे, राज्य सरकार ने, 2 जून, 2009 के अपने ज्ञापन के माध्यम से शारीरिक रूप से विकलांग व्याख्याताओं (नेत्रहीन) के 8 पदों को परिवर्तित करने का आदेश दिया। प्रिंसिपल, अकादमिक में प्रिंसिपल ग्रेड में रु. 16,400-22,400. इन पदों में वे पद भी शामिल हैं जिन पर याचिकाकर्ता लेक्चरर के पद पर थे। इन पदों के परिवर्तन के परिणामस्वरूप, याचिकाकर्ताओं को 24 जून, 2009 के आदेश के तहत अनुबंध पी-5 के तहत व्याख्याताओं (उन्नत) के रिक्त पद के खिलाफ नए परिवर्तित पदों के खिलाफ उनके मूल पोस्टिंग स्थान पर स्थानांतरित कर दिया गया था ( अनुलग्नक - पी ) .6). संवर्ग की स्वीकृत शक्ति में प्रधानाध्यापकों की 8 रिक्तियों के विरुद्ध, 24 जून, 2009 के एक अन्य आदेश (अनुलग्नक-पी.7) द्वारा आगे की पदोन्नति की गई है। याचिकाकर्ताओं ने आदेशों (अनुलग्नक-पी.5 और पी.6) को चुनौती दी है, जिसके तहत व्याख्याताओं (नेत्रहीन) के 8 पदों को

प्रिंसिपल, अकादमिक में परिवर्तित कर दिया गया है और याचिकाकर्ताओं को परिवर्तित पदों में से दो के विरुद्ध तैनात किया गया है। याचिका में मुख्य चुनौतियाँ इस प्रकार हैं:-

- (2) नियमों में प्राचार्य, शैक्षणिक का पद अस्तित्व में नहीं है।
- (3) परिवर्तित पदों के विरुद्ध याचिकाकर्ताओं की पोस्टिंग प्रत्यावर्तन के समान है।
- (4) प्रमोशन की आगे की संभावनाएं खत्म हो जाती हैं
- (5) कनिष्ठों को वरिष्ठों के ऊपर प्रधानाध्यापक के पद पर बिठाया गया।
- (6) शारीरिक दुर्बलता के कारण भेदभाव.

2) ) याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील श्री अरोड़ा का कहना है कि प्रिंसिपल का पद वैधानिक नियमों अर्थात् हरियाणा शिक्षा (कॉलेज कैडर) ग्रुप-ए, सेवा नियम, 1986 के तहत सेवा के कैडर पर आधारित है। नियम 3 संख्या से संबंधित है। और पद का चरित्र, नियम 7 योग्यता के साथ, जबकि नियम 9 भर्ती की विधि से संबंधित है। इन नियमों का प्रासंगिक उद्धरण यहां पुनः प्रस्तुत किया गया है: -

3) . पदों की संख्या और चरित्र.- सेवा में इन नियमों के परिशिष्ट में दर्शाए गए पद शामिल होंगे: बशर्ते कि इन नियमों में कोई भी बात सरकार के ऐसे पदों की संख्या में वृद्धि या कटौती करने या स्थायी या अस्थायी रूप से विभिन्न पदनाम और वेतनमान के साथ नए पद बनाने के अंतर्निहित अधिकार को प्रभावित नहीं करेगी।

योग्यताएँ.- (1) किसी भी व्यक्ति को सेवा में तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि उसके पास सीधी भर्ती के मामले में इन नियमों के परिशिष्ट बी के कॉलम 3 में निर्दिष्ट योग्यताएं और अनुभव न हो और उपरोक्त के कॉलम 4 में निर्दिष्ट योग्यताएं न हों। सीधी भर्ती के अलावा अन्य नियुक्ति के मामले में परिशिष्ट.

2) ) सेवा के प्रत्येक सदस्य को विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी और इस प्रयोजन के लिए वह लारियाना सरकारी शैक्षिक विभागीय परीक्षा नियमों 1976 द्वारा ,शासित होगा

9) भर्ती की विधि.- ( 1) सेवा में भर्ती की जाएगी:-

(a) संयुक्त निदेशक (कॉलेज) के मामले में उप निदेशक कॉलेज/प्रिंसिपल में से पदोन्नति द्वारा:

(b) उप निदेशक कॉलेजों/प्रिंसिपलों के मामले में-

(i) 25% सीधी भर्ती द्वारा; और

(ii) 75% कॉलेज व्याख्याताओं में से पदोन्नति द्वारा;

या

(c) सीधी भर्ती द्वारा प्रोफेसरों के मामले में: बशर्ते कि सरकार ऐसा कर सकती है. यदि भारत सरकार या किसी अन्य राज्य सरकार या विश्वविद्यालय से स्थानांतरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा किसी भी पद पर सीधी भर्ती या पदोन्नति द्वारा उपयुक्त उम्मीदवार उपलब्ध नहीं हैं।

(2) पदोन्नति द्वारा पदों पर सभी नियुक्तियाँ स्कोरियोरिटी-कम-क्रिट के आधार पर की जाएंगी और किसी भी व्यक्ति को केवल वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति का कोई अधिकार नहीं होगा।

(3) याचिकाकर्ताओं की ओर से तर्क दिया गया कि नियम 3 के अनुसार पदों की प्रकृति की संख्या परिशिष्ट 1 के तहत निर्दिष्ट है। पद का पदनाम उप निदेशक है। कॉलेज/प्रिंसिपल और

35 में निर्दिष्ट पदों की संख्या। प्राचार्य नाम से कोई अन्य पद नहीं। शैक्षणिक विकास मौजूद है और व्याख्याताओं के 8 और पदों को परिवर्तित करके, परिशिष्ट के तहत निर्दिष्ट कैडर पदों की संख्या 35 से अधिक हो गई है। श्री अरोड़ा के अनुसार नियमों के तहत प्राचार्यों के केवल 35 स्वीकृत पद उपलब्ध हैं और पदनाम और पदों की संख्या दोनों के संबंध में नियमों में संशोधन किए बिना सरकार कैडर की ताकत बढ़ाने या पद के लिए कोई अन्य पदनाम प्रदान करने की हकदार नहीं है। . उनका आगे तर्क यह है कि याचिकाकर्ता नियम 7 के तहत पदोन्नति के लिए योग्यता पूरी करते हैं और उनकी नियुक्ति नियम 9 के तहत 75% के निर्धारित कोटा के भीतर है और यदि रिक्तियों को बढ़ाने और नाम बदलने की अनुमति दी जाती है, तो यह नियम 9 के तहत निर्धारित कोटा का उल्लंघन है। उनके अनुसार स्वीकृत पदों में से 75% और 35% केवल पदोन्नति द्वारा भरे जा सकते हैं और विवादित आदेशों के आधार पर पदोन्नतियों का कोटा बढ़ जाता है जो वैधानिक नियमों का भी उल्लंघन है।

(4) याचिकाकर्ताओं की ओर से दलील दी गई है कि याचिकाकर्ताओं को प्रधानाचार्य के पद पर पदोन्नत करने के बाद अब फिर से व्याख्याता के पद पर वापस भेज दिया गया है और शिक्षण का समान कार्य करने के लिए उसी पद पर तैनात कर दिया गया है, जो प्रत्यावर्तन के समान है। यह भी तर्क दिया गया कि याचिकाकर्ताओं को उप निदेशक के पद पर पदोन्नति की और संभावना है। कॉलेज और फिर संयुक्त निदेशक. उनके प्रत्यावर्तन से महाविद्यालयों को नुकसान हुआ है। आईएल ने आगे तर्क दिया कि याचिकाकर्ताओं को व्याख्याताओं के पदों पर तैनात करके, उन्हें प्रिंसिपल के रूप में अपने कनिष्ठों के अधीन काम करने के लिए मजबूर किया जाता है। अंत में यह तर्क दिया गया कि याचिकाकर्ताओं को उन सभी पदोन्नत प्राचार्यों के खिलाफ शत्रुतापूर्ण और भेदभावपूर्ण व्यवहार दिया गया है।

(5) राज्य ने अपने जवाब में अपनी कार्रवाई को सही ठहराया है. बताया गया है कि लेक्चरर का पद क्लास-11 का पद है, जबकि प्रिंसिपल का पद क्लास-1 का पद है। याचिकाकर्ताओं की न तो स्थिति और न ही परिलब्धियाँ कम की गई हैं, उत्तरदाताओं की ओर से यह तर्क दिया गया है कि कॉलेज के प्राचार्य को विभिन्न प्रकार के कर्तव्यों का पालन करना पड़ता है। उन्हें वित्तीय मामलों को संभालने के अलावा प्रशासनिक कार्यों को करना और कॉलेज की दिन-प्रतिदिन की गतिविधियों का प्रबंधन करना होता है, जहां आंकड़ों, संख्याओं और बिलों आदि की बहुत सावधानी से जांच की जाती है। इली प्रिंसिपल एक आहरण और संवितरण अधिकारी हैं और उन पर वित्तीय और अन्य प्रशासनिक कार्यों को करने की भारी जिम्मेदारी डाली गई है और शारीरिक कमजोरी के कारण याचिकाकर्ता इन सभी कार्यों को करने में असमर्थ हैं। यह

यह भी कहा गया है कि प्राचार्य को छात्रों पर कड़ी निगरानी रखने के अलावा परीक्षाओं और अन्य मुद्दों की गोपनीयता बनाए रखने के लिए गोपनीय मामलों से भी निपटना होगा। उन्हें छात्रों की भी पहचान करनी होगी जिसे पूरा करना याचिकाकर्ताओं के लिए मुश्किल है।

(6) मैंने पक्षों के विद्वान वकीलों को विस्तार से सुना है।

(7) संसद ने अधिनियम बनाया है. विकलांग व्यक्तियों को विभिन्न सुरक्षा और सुविधाएं प्रदान करने की दृष्टि से विकलांग व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 (इसके बाद इसे अधिनियम कहा जाएगा)। अधिनियम का अध्याय 6 रोजगार से संबंधित है। धारा 32 उपयुक्त सरकार को प्रतिष्ठानों में विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षित पदों की पहचान करने का अधिकार देती है। धारा 33 विकलांग व्यक्तियों के लिए 3% आरक्षण का प्रावधान करती है। यह खंड निम्नलिखित तीन प्रकार की विकलांगताओं को निर्दिष्ट करता है-

(i) अंधापन या कम दृष्टि;

(ii) श्रवण बाधित;

(iii) लोकोमोटर विकलांगता या सेरेब्रल पाल्सी।

(8) प्रत्येक विकलांगता के लिए 1% आरक्षण निर्धारित है। हालाँकि, धारा 33 का प्रावधान, उपयुक्त सरकार को किसी भी विभाग या प्रतिष्ठान में किए गए कार्य के प्रकार को ध्यान में रखते हुए किसी भी प्रतिष्ठान को इस धारा के प्रावधानों से छूट देने की अनुमति देता है। ऐसी छूट केवल एक अधिसूचना द्वारा ही हो सकती है। अधिनियम की धारा 39 सरकारी शैक्षणिक संस्थानों और सरकार से सहायता प्राप्त करने वाले अन्य शैक्षणिक संस्थानों पर विकलांग व्यक्तियों के लिए कम से कम 3% सीटें आरक्षित करने का दायित्व लगाती है। इन तीनों खंडों को एक साथ पढ़ने से एक निष्कर्ष निकलता है कि विकलांगता से पीड़ित व्यक्तियों के लिए आरक्षित पद की पहचान करना और ऐसे पदों के लिए आरक्षण करना उपयुक्त सरकार का वैधानिक दायित्व है। धारा 39 विशेष रूप से राज्य सरकार को सभी शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण देने के लिए बाध्य करती है

और यह 3% से अधिक हो सकता है। हालाँकि, धारा 33 का प्रावधान, सरकार को प्रदर्शन किए जाने वाले कर्तव्यों की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, एक अधिसूचना द्वारा किसी भी प्रतिष्ठान को आरक्षण के दायित्व से छूट देने की अनुमति देता है। माना कि राज्य सरकार ने प्रधानाध्यापकों की रिक्तियां दृष्टिहीन (नेत्रहीन) दिव्यांगों के लिए आरक्षित कर दी हैं। यह आरक्षण धारा 32, 33 और 39 के प्रावधानों के अनुसार है। इस श्रेणी के पद को छूट देने के लिए धारा 33 के प्रावधान के तहत कोई वैधानिक अधिसूचना नहीं है।

धारा 33 के प्रवर्तन से किसी भी स्थापन इसके विपरीत शिक्षण संस्थानों में प्रधानाचार्यों के पद दृष्टिहीनों की आरक्षित श्रेणी से भरे गए हैं। इस तरह का आरक्षण करने के बाद, नेत्रहीन व्यक्तियों को अपने कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थता की दलील पर प्रश्नगत पद पर नियुक्ति के लाभ से वंचित करना अनुचित है। प्रधान पद के लिए दृष्टिबाधित व्यक्तियों का आरक्षण करना धारा 33 के अनुरूप है। यदि शासन की दृष्टि से ऐसे दृष्टिहीन व्यक्ति कर्तव्य पालन करने में असमर्थ हैं तो धारा के परन्तुक के अधीन वैधानिक अधिसूचना जारी करना आवश्यक था। 33. ऐसी कोई अधिसूचना जारी नहीं की गई है। इसी तरह का एक विवाद इस न्यायालय द्वारा बलविंदर सिंह बनाम पंजाब राज्य और अन्य (1) के मामले में तय किया गया है , जिसमें निम्नलिखित टिप्पणियाँ की गई हैं: -“

“5. बार में संबोधित तर्कों पर विचार करने के बाद, हम संतुष्ट हैं कि याचिकाकर्ताओं का दावा पूरी तरह से उचित है। 2 मार्च, 2001 के निर्देश स्पष्ट रूप से 1995 के अधिनियम की धारा 33 के आदेश के विपरीत हैं। 1995 के अधिनियम के प्रावधानों से छूट केवल सरकार के हाथों एक अधिसूचना द्वारा ही दी जा सकती है। वर्तमान मामले में दायर याचिका के अनुसार ऐसी कोई अधिसूचना जारी नहीं की गई है। चूंकि 1995 के अधिनियम की धारा 33 के प्रावधानों के संदर्भ में, राज्य सरकार ने 9 मार्च, 2001 को एक विज्ञापन जारी किया था जिसमें स्पष्ट रूप से संकेत दिया गया था कि रिक्तियां विकलांग उम्मीदवारों, अन्य बातों के अलावा कम दृष्टि/नेत्रहीन उम्मीदवारों से भरी जाएंगी, यह है अब प्रतिवादी के लिए अनुमति नहीं है - चयन की प्रक्रिया में याचिकाकर्ता द्वारा प्राप्त योग्यता के अनुसार याचिकाकर्ता को नियुक्ति देने से इनकार करना राज्य के लिए अस्वीकार्य है।”

(9) ऊपर उल्लिखित कानूनी प्रस्तावों के अलावा, यह भी देखा गया है कि मुख्य याचिकाकर्ताओं को विभिन्न प्रकार के कर्तव्यों और ज्यादातर प्रशासनिक कर्तव्यों का पालन करना पड़ता है। उन्हें पढ़ाने की शायद ही आवश्यकता हो। अनुलग्नक -पी.5 और पी.6 के माध्यम से याचिकाकर्ताओं को प्रधानाचार्य के रूप में कार्य करने के उनके अधिकार से वंचित कर दिया गया है और उन्हें फिर से शिक्षण का काम सौंपा गया है जो वे व्याख्याता के रूप में कर रहे थे। हालाँकि, उनकी परिलब्धियाँ कम नहीं हुई हैं, लेकिन उनकी स्थिति निश्चित रूप से बदल जाती है और जब उन्हें सभी प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए प्रिंसिपल के अधीन काम करने की आवश्यकता होती है, तो

उनका हिस्सा कम हो जाता है। यहां तक कि उनसे जूनियर को भी प्रिंसिपल नियुक्त किया जा सकता है और वे 0) 2004 (2) आर.एस.जे.216

उसके प्रशासनिक नियंत्रण में रखा जाएगा जो कि कानूनन अनुमति योग्य नहीं है। यह परिलब्धियों की रक्षा करने और प्रिंसिपल के पदनाम को बरकरार रखने से तकनीकी अर्थ में उलटफेर नहीं हो सकता है, लेकिन वास्तव में यह याचिकाकर्ताओं को प्रिंसिपल के पद पर दिए गए विभिन्न कार्यों और कर्तव्यों से वंचित करने के समान है। वैधानिक नियमों के तहत पद का पदनाम प्राचार्य है। कोई प्रिंसिपल नहीं है। शैक्षणिक विकास या प्राचार्य. प्रशासन या किसी अन्य प्रकार के प्राचार्य द्वारा नियम को दरकिनार करने के लिए इस तरह की कल्पना करना अनुचित है।

(10) तथ्य की बात यह है कि प्रिंसिपल को समान स्तर के किसी अन्य प्रिंसिपल के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन किया जा रहा है और याचिकाकर्ताओं से कनिष्ठ व्यक्ति को कॉलेज में प्रिंसिपल नियुक्त किया जा सकता है। यह याचिकाकर्ताओं के लिए एक शर्मनाक स्थिति होगी।' इस प्रकार, उत्तरदाताओं की कार्रवाई प्रत्यावर्तन के समान है। अन्यथा भी प्राचार्य का पद. नियमों में शैक्षणिक विकास दस्तावेज़ मौजूद नहीं हैं। 1 आईओ हम देखें. मैं परिशिष्ट ए के साथ पढ़े गए नियम 10 के तहत निर्धारित पद के कोटा में बदलाव के संबंध में श्री अरोड़ा के तर्क से सहमत नहीं हूं। नियम 3 का प्रावधान सरकार को पदों की संख्या में वृद्धि या कटौती करने या सृजन करने की अनुमति देता है। विभिन्न पदनामों के साथ भी नई पोस्ट। ऐसा करने की शक्ति सरकार को प्रदान की गई है, लेकिन इस शक्ति का प्रयोग सरकार के कामकाज के नियमों के अनुसार सरकार में सक्षम प्राधिकारी द्वारा एक वैधानिक अधिसूचना द्वारा कानून के अनुसार किया जाना चाहिए। निश्चित रूप से, सरकार के पास अधिकार है कि वह डिलक्रेट पदनामों के साथ नए पद सृजित कर सकती है और यहां तक कि मौजूदा पदों की संख्या बढ़ा या घटा भी सकती है, लेकिन इसे नियमों में संशोधन करके कानून के अनुसार किया जाना चाहिए। ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं अपनाई गई है. Anncxurc-P.5 प्रशासनिक संचार की प्रकृति में केवल एक कार्यालय ज्ञापन है। आईएल किसी नियम या कानून का दर्जा हासिल नहीं कर सकता.

(11) यह स्थापित कानून है कि प्रशासनिक निर्देश वैधानिक प्रावधानों पर हावी नहीं हो सकते या उनकी जगह नहीं ले सकते। अगर सरकार का इरादा इन पदों को धारा 33 के दायरे से बाहर लाने का था ताकि विकलांग व्यक्तियों के लिए एक अलग तरह का पद सृजित किया जा सके, धारा 33 के प्रावधानों के तहत एक वैधानिक अधिसूचना जारी करना उचित था या भर्ती के नियमों को ध्यान में रखना चाहिए था। संशोधन किया गया. हालाँकि, उत्तरदाता कानून का उल्लंघन करते हुए केवल पोस्ट को परिवर्तित करने के लिए प्रशासनिक निर्देश जारी करते हैं। इस तरह का सहारा कानून द्वारा उचित नहीं है। आक्षेपित संचार (Anncxurcs-P5 और P.6) हैं। इस प्रकार, इस आधार पर भी उसे अलग रखा जा सकता है।

अमर कौर आर. पंजाब राज्य और ओटियर्स 115 (अजा/लांबा, जेजे)

(12) अधिनियम की धारा 47 सरकारी रोजगार में विकलांग व्यक्तियों के खिलाफ भेदभाव पर रोक लगाती है। धारा 47 की उपधारा 2 में स्पष्ट रूप से प्रावधान है कि किसी व्यक्ति को केवल उसकी विकलांगता के आधार पर पदोन्नति से वंचित नहीं किया जा सकता है। भले ही किसी प्रतिष्ठान में किसी विशेष पद के लिए विकलांग व्यक्ति को केवल विकलांगता के कारण पदोन्नति से वंचित किया जा सकता है, यह केवल वैधानिक अधिसूचना के माध्यम से धारा 47 के प्रावधानों से प्रतिष्ठान को छूट प्रदान करके किया जा सकता है। वास्तव में वही बात है धारा 33 के प्रावधानों के तहत निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया जाना है। इस धारा के तहत भी ऐसी कोई अधिसूचना जारी नहीं की गई है। याचिकाकर्ताओं के साथ कानून में निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए बिना केवल उनकी विकलांगता के आधार पर अन्य पदोन्नत प्रधानाध्यापकों के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है।'

(13) तथापि। मैं याचिकाकर्ताओं की इस दलील को स्वीकार करने में असमर्थ हूँ कि उनकी पदोन्नति की आगे की संभावनाएं खतरे में हैं। 1 कम होने से आगे पदोन्नति के अवसर खतरे में पड़ जाएंगे, यह रिट याचिका में निर्दिष्ट नहीं है और न ही न्यायालय के समक्ष ठोस तर्क दिया गया है। अतः इस विवाद में कोई दम नहीं है।

(14) परिस्थितियों की समग्रता को ध्यान में रखते हुए, विवादित आदेश (अनुलग्नक-पी.5 और पी.6) को रद्द किया जाता है। इस तरह का रद्दीकरण सरकार को विकलांगता अधिनियम की धारा 33 या धारा 47 के संदर्भ में प्रतिष्ठान को छूट देने से नहीं रोकेगा।

(15) उपरोक्त तरीके से याचिका स्वीकार की गई।

**अस्वीकरण** : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

जसमीत कौर

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

(Trainee Judicial Officer)

कैथल, हरियाणा